









# मध्य प्रदेश चुनाव में कई पार्टी की हुई एंट्री

## राहुल संपाल

साल के अंत में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां तेज हो चली हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा ने जहां 39 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जबकि कांग्रेस संघवितों के बायोडाटा को खंगाल रही है। वहाँ, समाजवादी पार्टी-बहुजन समाज पार्टी ने भी उम्मीदवारों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। वैसे तो एमपी के चुनाव में सीधा मुकाबला कांग्रेस-भाजपा के बीच ही होता है। लेकिन कई बार बहुजन समाज पार्टी-समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी प्रदेश में अपनी ताकत का एहसास भी करवा चुकी है। आम आदमी पार्टी भी उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया से गुजर रही है तो आदिवासी युवाओं के बीच काम करने वाला संगठन जयस उन क्षेत्रों पर नजर गढ़ाए हुए हैं जहां आदिवासी बोटरों की संख्या ज्यादा है।

मध्यप्रदेश के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर छोटे दल अपनी ताकत प्रदर्शने की तैयारी में जुटे हुए हैं। राज्य के दो प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी विधानसभा वार आकलन में जुटे हुए हैं। जिन सीटों पर हार मिली इसका ब्योरा जुटाया जा रहा है तो वहाँ वर्तमान विधायकों की क्या स्थिति है। इसकी समीक्षा का दौर जारी है। कांग्रेस-भजपा चुनाव में जीत की रणनीति बनाने के साथ उम्मीदवारों के चयन में लगे हैं तो दूसरी ओर सपा-बसपा उम्मीदवारों के फैसले भी करने लगे हैं। बहुजन समाज पार्टी के सात उम्मीदवारों की सूची भी आ गई है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने भी चार सीटों के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। संभवना इस बात की जताई जा रही है कि अगस्त माह में ही सपा-बसपा अन्य उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है।

मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपना खोया हालांकि, इसमें से एक सजाव सिंह भाजपा का समर्थन दे चुके हैं।

बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बाद अब समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सपा ने छतरपुर की राजनगर विधानसभा सीट, दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट, निवाड़ी और भिंड की मेहगांव सीट पर प्रत्याशी मैदान में उतारें हैं। यह चारों सीटें बुंदेलखण्ड और ग्वालियर-चंबल क्षेत्र की हैं। पार्टी ने जिन चार सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है वे सभी यूपी की सीमा से सटे हुए हैं। निवाड़ी, राज नगर, भांडेर बुंदेलखण्ड क्षेत्र में हैं, वहाँ मेहगांव ग्वालियर-चंबल क्षेत्र का हिस्सा है। चारों विधानसभा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे होने से यहाँ पार्टी को सफलता मिलने की उम्मीद है।

जनाधार पाने में जुटी है। ग्वालियर-चंबल, विंध्य और बुंदेलखण्ड क्षेत्र में पार्टी का प्रभाव रहा है। हाल के वर्षों में बसपा का अपना कोर वोट बैंक छिटक गया है। यही वोट बैंक इन क्षेत्रों में कभी कांग्रेस तो कभी भाजपा की जीत का कारण बनता रहा। 2018 के चुनाव में ग्वालियर-चंबल क्षेत्र में बसपा के परंपरागत दलित वोट बैंक का झुकाव कांग्रेस की तरफ हुआ था। इससे बसपा के साथ भाजपा को भी नुकसान हुआ। जबकि विंध्य में बसपा के कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ। भाजपा को इस क्षेत्र में बढ़त मिल गई। कांग्रेस इस इलाके से केवल सात सीटें ही जीत सकी। लेकिन अब बसपा 2023 के चुनावों में अपना खोया

# उत्तर प्रदेश का बदल रहा है तसवार...लाकन अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी

## उमरा घतुवदा

इस बिडबना नहीं तो क्या कहग क समृद्ध सास्कृतक विवासत, गण-यमुना आर घारधर जसा सदानारा नदियों का उपजाऊ मैदानों के बावजूद उत्तर प्रदेश की ख्याति बीमारू यानी रोगी राज्य के रूप में रही। उत्तर प्रदेश राजनीतिक रूप से बेहद सचेत लोगों का भी राज्य रहा है। माना जाता है कि जिस इलाके की जनता राजनीतिक रूप से ज्यादा सचेत होती है, वहां विकास की धारा बहती रहती है। माना तो यह भी जाता है कि प्रभावी राजनीति जिस इलाके का प्रतिनिधित्व करती है, उस इलाके में विकास की गति अपने आप तेज हो जाती है। उत्तर प्रदेश प्रभावी राजनीति का भी केंद्र रहा है। देश को उसने आठ प्रधानमंत्री दिए, जिनमें से छह की जन्मभूमि भी उत्तर प्रदेश की माटी रही है, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश अपनी अराजक संस्कृति और भ्रष्टाचारी शासन व्यवस्था के लिए ज्यादा जाना जाता रहा है। लेकिन अब इसी उत्तर प्रदेश की छवि बदलने लगी है। इसका श्रेय निश्चित तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोच को दिया जा सकता है। जिसकी वजह से ना सिर्फ यहां के अराजक माहौल में बदलाव आने लगा है, बल्कि इस राज्य को अब उद्योग और कारोबार के लिए मुफीद माना जाने लगा है। अस्सी के दशक में जब उत्तर प्रदेश के ही संसदीय नुमाइँदे राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तब अर्थशास्त्री आशीष बोस ने बीमारू राज्य की परिकल्पना पेश की थी। बीमार यानी रूग्ण से प्रेरित यह बीमारू शब्द बुनियादी रूप से चार राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इन्हीं में से तीन राज्य अलग होकर अब सात राज्य हो गए हैं। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखण्ड, छत्तीसगढ़ और झारखण्ड के अपने मूल राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से अलग होने के बावजूद जितनी तेज तरकी की उम्मीद की जा रही थी, वैसी नजर नहीं आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश इनमें से अलग राह पर चलता दिख रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए योगी आदित्यनाथ की कड़क और कुशल शासन व्यवस्था को श्रेय दिया जा सकता है। किसी भी राज्य में कारोबार और उद्योग कब पनपता है, जब वहां की कानून-व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त होती है, वहां बुनियादी ढांचा मसलन सड़क, बिजली और पानी की सहूलियत होती है। इसके साथ ही मेडिकल यानी चिकित्सा सुविधा भी बेहतर होनी चाहिए। कुछ साल पहले तक उत्तर प्रदेश में बिजली छोड़ सारे संसाधन थे, लेकिन कानून-व्यवस्था बेहद लचर थी। अराजक व्यक्तियों और समूहों के इशारे पर ही जैसे राज्य की कानून-व्यवस्था चलती थी। राजनीति एक तरह से उनकी पिछलगूँथी। बिजली राज्य की राजधानी लखनऊ और कुछ-एक वीआईपी माने जाने वाले शहरों में ही होती थी। बाकी समूचा राज्य बिजली की आंख-मिचौनी देखता था। सरकारी दफ्तरों में बाबुओं की मनमानी चलती थी। लेकिन साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले कानून-व्यवस्था की हालत की तरफ ध्यान दिया। ऐसा नहीं कि योगी के प्रयासों से कानून-व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश स्वर्ग बन गया है। लेकिन यह भी सच है कि कानून का भय अब अराजक समूहों में आया है। सड़कें दुरुस्त हुई हैं। हालांकि छोटे इलाकों और गांवों को जाड़े वाली सड़कों पर अब भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिजली की हालत भी ठीक हुई है। अब समूचे प्रदेश में बिजली है। इसका असर जमीनी स्तर पर दिखने लगा है। अब शेयर बाजार में उत्तर प्रदेश के निवेशक छा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डीमैट अकांउंट का आंकड़ा करीब 12 करोड़ हो चुका है। 23 करोड़ की जनसंख्या वाले राज्य में 12 करोड़ खातों के जरिए शेयर बाजार में दस्तक देना मामूली बदलाव नहीं है। बीते अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में इक्कीटी टेंड की वजह से 1.26 लाख नए निवेश जुड़े हैं।

## मोदी को टक्कर दे पाएगा इंडिया गठबंधन, आज हुए चुनाव तो किसको मिलेंगी किनती सीटें?

अंकित सिंह

इंडिया टुडे-सीवोटर के सर्वे के अनुसार विपक्षी गठबंधन इंडिया भारतीय जनता पार्टी को हराने में सक्षम नहीं दिख रहा। सर्वेक्षण से पता चला कि 54 प्रतिशत लोगों का मानना है कि इंडिया ब्लॉक भाजपा को हरा नहीं पाएगा, जबकि सिर्फ 33 प्रतिशत को ऐसा होने की उम्मीद है। गठबंधन का नया नाम इंडिया एक महाने प्रत्येक लोगों में प्रकृत भालू वैनर्स में साझे आया था विपक्षी नेता के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के प्रदर्शन को उत्कृष्ट माना है। जबकि 18 प्रतिशत उत्तराधिकारी ने विपक्षी नेता के रूप में उनका प्रदर्शन अच्छा, 15 प्रतिशत ने औसत और 27 प्रतिशत ने खराब पाया। सर्वे में 44 फीसदी लोगों ने कहा कि भारत जोड़े यात्रा के बाद राहुल गांधी की छवि में सुधार आया है। 33 फीसदी का मानना है कि राहुल की छवि में कोई बदलाव नहीं हुआ।



प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के प्रदर्शन से संतुष्ट हैं। 13 प्रतिशत लोगों ने पीएम मोदी के प्रदर्शन को औसत पाया, और 22 प्रतिशत ने इसे खराब बताया।

### मोदी का विकल्प कौन?

इस सर्वेक्षण में यह भी पूछा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर आप किसे देखते हैं, 29 प्रतिशत लोगों ने केंद्रीय गढ़ मंत्री अमित शाह का

पहल बगलुरु में एक भव्य बठक में समन आया था, जहां एकजुट विपक्ष ने अगले साल लोकसभा चुनाव में बदलाव नहीं हुआ है।  
**किसको कितनी सीटें**  
29 प्रतिशत लाना न करने वाला जानत शाह का नाम लिया जबकि योगी अदित्यनाथ का 26 प्रतिशत लोटे ने लिया है। दिल्ली के लागे 15

भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिका (एनडीए) से मुकाबला करने की अपनी

# महाराष्ट्र में चाचा-भतीजे ने ऐसी गुगली डाली कि सारे दल बोल्ड हो गये

नीरज कुमार दुखे

# नए बने गठबंधन में क्या जु़़ड़ा और क्या घटा?

कांश राजनीतिक विषय

की 24 और डीएमके की 16 और एनसीपी की 9 सीटें थीं। इसलिए न एनडीए को बहुमत मिला था, न कांग्रेस गठबंधन को। चुनाव के बाद यूपीए बना, जिसमें कांग्रेस के पुराने पहयोंगियों के अलावा पीडीपी, टीआरएस, एआईएमआईएम, तृणमूल कांग्रेस, झारखण्ड विकास मोर्चा, केरल का जनता दल डेमोक्रेटिक, एमडीएमके, टीआरएस, पीपीएमके और बसपा शामिल हुए। लेकिन इन सब की संसंघीय भी कुल मिला कर 218 ही हुई थी, तब वापर्पंथी दलों के 59 सांसदों और समाजवादी पार्टी के 36 सांसदों के बाहरी समर्थन से यूपीए की सरकार बनी थी। क्या 2024 में एनडीए के मुकाबले नया विपक्षी गठबंधन बनने से 2004 वाली स्थिति पैदा हो सकती है? जैसे वाजपेयी के रासनकाल में देश ने इन्फास्ट्रक्चर और आर्थिक क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन जैसे इन उपलब्धियों के बूते वाजपेयी 2004 में नहीं जीत पाए थे, वैसे इन उपलब्धियों के बूते मोदी 2024 में नहीं जीत पाएंगे। कहा जा रहा है कि इंडिया नाम से जो नया गठबंधन बना है, उससे ज्यादा नहीं तो 2004 वाले नतीजे तो आ ही जाएंगे। लेकिन यह याद खबाना चाहिए कि नए गठबंधन में शामिल

गठबंधन भाजपा का कुछ नहा बिगड़ पाएगा, लाकन व लोग जो 2024 की तुलना 2004 से कर रहे हैं, वे जमीनी हकीकत से बहुत दूर हैं। तब भाजपा ने कभी 200 का आंकड़ा पार नहीं किया था, जबकि अब भाजपा 300 का आंकड़ा पार कर चुकी है। इनमें से 224 सीटों पर भाजपा ने 51 प्रतिशत से ज्यादा वोट हासिल किया था, जो यह साबित करता हैं किरोधी दल मिल कर भी 224 सीटों पर भाजपा से पीछे हैं। इंडिया नाम का विपक्षी गठबंधन मोदी को चुनौती जरूर देगा, लेकिन वह चुनौती 2004 जैसी नहीं हो सकती। हालांकि इस नए गठबंधन में वही सभी दल हैं, जिन्होंने 2004 में यूपीए की सरकार बनवाई थी, लेकिन इस बीच गंगा में बहुत पानी बह चुका है। 18 जुलाई को जब यूपीए भंग हुआ, तब उसमें उद्घव ठाकरे की शिवसेना समेत 19 राजनीतिक दल और लोकसभा में 108 सांसद थे। 18 जुलाई को बने इंडिया नाम के गठबंधन में यूपीए के 19 दलों के अलावा समाजवादी पार्टी, आरएलडी, दो कम्युनिस्ट पार्टीयां, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और जेडीयू शामिल हुई हैं। इन सभी दलों के लोकसभा में 43 सदस्य हैं। 2004 के बाद यूपीए में रही बहुजन समाज पार्टी, टीआरएस, एआईएमआईएम और जेडीएस नए बने इंडिया

पाए। जाजन खान के इसाना दून से खाला ऊर मुस्सान बहुल रामपुर सीट भी उपचुनाव में नहीं बचा पाए। सपा की सहयोगी आरएलडी के पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी बसपा, सपा का समर्थन होने के बावजूद खुद ही चुनाव हार गए थे। जाटों के किसान आन्दोलन के बावजूद एरएलडी विधानसभा की 33 सीटें लड़ कर सिर्फ आठ जीत पाई थी। इस बीच ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं, जिससे अखिलेश यादव 2019 और 2022 से काफी कमजोर हुए हैं। अब बची जेडीयू और आम आदमी पार्टी। जेडीयू पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन करके 16 सीटें जीती थी, 2014 में उसका भाजपा से गठबंधन नहीं था, तो वह बिहार में सफ़ हो गई थी। विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उसकी सीटें घट गई। अभी हाल ही के दो महीनों में उपेन्द्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जेडीयू का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए हैं। राजद और जेडीयू के गठबंधन के चलते मुकाबला कड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन बिहार में भी भाजपा का पलड़ा हार हाल में भारी है, क्योंकि 2014 के उसके गठबंधन के साथी एनडीए में लौट आए हैं।

नए दल नए यूपीए में शामिल हुए हैं, उनकी अपने अपने राज्यों में क्या स्थिति है। कम्युनिस्ट पार्टिया बंगाल और त्रिपुरा में खत्म हो चुकी हैं, केरल में भी पिछली बार सिर्फ एक लोकसभा सीट जीती थी, बाकी सारे देश में भी उसका प्रभाव खत्म हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस का जरूर पश्चिम बंगाल में पलड़ा भारी है, पिछली बार वह कांग्रेस, कम्युनिस्टों और भाजपा को हरा कर 42 में से 22 सीटें जीती थी, जबकि भाजपा 18 सीटें जीती थी, कांग्रेस 2 सीटें जीती थी। बंगाल में अगर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिल कर लड़ते हैं तो जरूर भाजपा के साथ कड़ा मुकाबला होगा और इंडिया गठबंधन की दो-चार सीटें बढ़ भी सकती हैं, लेकिन ममता कम्युनिस्टों को समझौते में कोई सीट नहीं छोड़ने वाली। चौथी पार्टी है समाजवादी पार्टी, जो बसपा से गठबंधन के बावजूद पिछली बार 5 लोकसभा सीटें जीत पाई थी। बसपा से गठबंधन टूटने के बाद अखिलेश यादव ने जब विधानसभा सीट जीतकर अपनी लोकसभा सीट खाली की तो उपचुनाव में अपनी खुद की लोकसभा सीट नहीं बचा पाए। आजम खान के इस्तीफा देने से खाली हुई मुस्लिम बहुल रामपुर सीट भी उपचुनाव में नहीं बचा पाए। सपा की सहयोगी आरएलडी के पल्ले कुछ भी नहीं है, उसके अध्यक्ष जयंत चौधरी बसपा, सपा का समर्थन होने के बावजूद खुद ही चुनाव हार गए थे। जाटों के किसान आन्दोलन के बावजूद आरएलडी विधानसभा की 33 सीटें लड़ कर सिर्फ आठ जीत पाई थी। इस बीच ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के साथ छोड़कर एनडीए में जा चुके हैं, जिससे अखिलेश यादव 2019 और 2022 से काफी कमजोर हुए हैं अब बची जेडीयू और आम आदमी पार्टी। जेडीयू पिछली बार भाजपा के साथ गठबंधन करके 16 सीटें जीती थी, 2014 में उसका भाजपा से गठबंधन नहीं था, तो वह बिहार में साफ़ हो गई थी। विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन के बावजूद उसकी सीटें घट गईं। अभी हाल ही के दो महीनों में उपेन्द्र कुशानाहा और जीतन राम माझी जेडीयू का साथ छोड़कर एनडीए में चले गए हैं। राजद और जेडीयू के गठबंधन के चलते मुकाबला कड़ा जरूर हो जाएगा, लेकिन बिहार में भी भाजपा का पलड़ा हर हाल में भारी है, क्योंकि 2014 के उसके गठबंधन के साथी एनडीए में लौट आए हैं।

# युवा/कैरियर



# अर्थशास्त्र

## हर क्षेत्र की जरूरत

### प्रमुख संस्थान

इसमें संबंधित कोर्स करने वाले प्रमुख संस्थान निम्न हैं—  
दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, नई दिल्ली वेबसाइट— [www.econdse.org](http://www.econdse.org)  
जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू), नई दिल्ली वेबसाइट— [www.jnu.ac.in](http://www.jnu.ac.in)  
ब्राह्मण दिल्ली यूनिवर्सिटी (बीएचयू), वाराणसी वेबसाइट— [www.bhu.ac.in](http://www.bhu.ac.in)  
प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता वेबसाइट— [www.presiuniv.ac.in](http://www.presiuniv.ac.in)  
संस्टीफन्स कॉलेज, नई दिल्ली वेबसाइट— [www.ststephens.edu](http://www.ststephens.edu)  
यूनिवर्सिटी ऑफ बाबू, मुंबई वेबसाइट— [www.mu.ac.in](http://www.mu.ac.in)  
ईडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता वेबसाइट— [www.isical.ac.in](http://www.isical.ac.in)  
श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, नई दिल्ली वेबसाइट— [www.srcc.edu](http://www.srcc.edu)  
सिक्कियोसिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पुणे वेबसाइट— [www.sse.ac.in](http://www.sse.ac.in)

### कराए जाने वाले कोर्स

- बीए (इकोनॉमिक्स/विजनेस इको./डेवलपमेंट इको.)
- बीए/बीएससी (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स
- एम इन इकोनॉमिक्स/अल्लाइड इको./विजनेस इको./ईडियन इको.
- एमएससी इको./विजनेस एंड कॉर्पोरेट इको.
- एमफिल/पीएचडी इन इकोनॉमिक्स/विजनेस इको./अप्लाइड इको.
- एमवीई (मास्टर ऑफ विजनेस इकोनॉमिक्स)
- एमएफसी (मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल)
- एमवीए विजनेस इकोनॉमिक्स
- पीजी डिल्सोमा इन इको./अल्लाइड इको./
- ग्लोबल विजनेस।

### कहां-कहां हैं अवसर

इकोनॉमिक्स में सफलतापूर्वक अंडरग्रेजुएट डिग्री हासिल करने पर फ्रेफशनल्स या तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म की ओर खुब करते हैं या इकोनॉमिक-फाइनेंशियल रिसर्च, बैंकिंग एवं कार्य के स्वरूप अपने विज्ञान का उनका रहना। यहाँ विज्ञान का सहभाग भी है। यदि वे लीक से थोड़ा अलग हट कर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए जर्नलिज्म व लॉ इंस्टीट्यूट बैहर साबित हो सकती है। कई ऐसे एजीओ व एक्सपोर्ट ऑफिस हैं, जो इकोनॉमिक बैंकिंग वाले छात्रों को अपने यहाँ जाकर देते हैं। किसी कांलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग में भी कारियर बनाया जा सकता है।

सकते हैं। इसके अलावा वे चाहें तो कई प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सर्विस, इकोनॉमिक एवं स्टैटिस्टिक सर्विस आदि में भाग्य आजमा सकते हैं। इससे समय सबसे अधिक प्रचलन पॉर्टफोलियो एवं रिसर्च एवं कंसल्टेंट आदि की है, लेकिन इस स्तर पर चौंतियां भी खुब हैं। ग्रेजुएशन के बाद कुछ डिलोमा लेवल के कोर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है।

कौन हैं इकोनॉमिस्ट

एक इकोनॉमिस्ट अपनी रिसर्च एवं एकत्र किए डाटा के आधार पर देश के संदर्भ में नीतियां तैयार करता है और उसे लागू करने के उपयोग भी बताता है। उसका यह कार्य रिपोर्ट, स्टैटिस्टिकल चार्ट, कम्प्यूटर व रिसर्च टीम की सहायता से होता है।

योग्यता जो दिलाए प्रवेश

इकोनॉमिक्स की फैलिंग में जो भी प्रचलित कोर्स हैं, उनमें दाखिला ग्रेजुएशन के बाद ही मिलता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन लेवल पर भी इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है, जबकि इकोनॉमिक्स के बाद हायर लेवल के कोर्स में प्रवेश मिलता है। यदि छात्र ने सफलतापूर्वक पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स कर लिया है तो वह एमफिल/पीएचडी करने के लिए योग्य हो सकता है। कुछ डिलोमा लेवल के कोर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें ग्रेजुएशन के बाद ही किया जा सकता है।

**किसी** भी देश की मजबूती का आकलन उसकी अर्थव्यवस्था से किया जाता है। अर्थव्यवस्था तभी मजबूत हो पाती है, जब उस देश की आर्थिक नीतियां व कार्यशैली सुचारू ढांग से संचालित हो रही हैं। इसमें जरा सा असुलत होने पर अर्थव्यवस्था पटरी से उतरने लगती है और देश को महांगाई व कर्ज लेने आदि का दंश झेलना पड़ता है। भारत के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आर्थिक उदारीकरण के बाद देश की अर्थव्यवस्था में तेजी से बदलाव नजर आने लगा। देश में उद्योग-धंधों को भी विकास का नया आयाम मिल गया। साथ ही यहाँ की अर्थव्यवस्था भी पहले की अपेक्षा सुदृढ़ होती गई। इसका सारा श्रेय यहाँ के अर्थसास्त्रियों को जाता है। इन अर्थसास्त्रियों ने देश के मुताबिक यहाँ की अर्थव्यवस्था को न सिर्फ गति प्रदान की, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक पहचान भी दिलाई। यही कारण है कि यहाँ पर इकोनॉमिक्स एक आकर्षक करियर क्षेत्र के रूप में युवाओं को लुभा रहा है।

**कराए जाने वाले कोर्स**

इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वैसे तो कराए जाने वाले कई कोर्स मौजूद हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रचलन पॉर्टफोलियो लेवल के कोर्स का है। इसके कई अलग-अलग क्षेत्र भी मौजूद हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय सहित कई ऐसे संस्थान हैं, जो ग्रेजुएट लेवल पर इकोनॉमिक्स की पढाई करते हैं। जो छात्र हायर लेवल पर पढ़ने के लिए चुनौती है, वे एनार्सीमेंटल इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इंश्योरेंस एंड एक्शनियल साईंस, एम्प्रेसिव बैंकिंग, फाइनेंस व बिजनेस इंडियन्स एंड मैनेजमेंट, इंस्टेनेशनल मार्केटिंग तथा ग्लोबल बिजनेस ऑफरेशन आदि में जा सकते हैं। कुछ अन्य कोर्स निम्न हैं—

- बीए (इकोनॉमिक्स/विजनेस इको./डेवलपमेंट इको.)
- बीए/बीएससी (ऑनर्स) इकोनॉमिक्स
- एम इन इकोनॉमिक्स/अल्लाइड इको./बिजनेस इको./ईडियन इको.
- एमएससी इको./विजनेस एंड कॉर्पोरेट इको.
- एमफिल/पीएचडी इन इकोनॉमिक्स/विजनेस इको./अप्लाइड इको.
- एमवीई (मास्टर ऑफ विजनेस इकोनॉमिक्स)
- एमएफसी (मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल)
- एमवीए विजनेस इकोनॉमिक्स
- पीजी डिल्सोमा इन इको./अल्लाइड इको./
- ग्लोबल बिजनेस।

### कहां-कहां हैं अवसर

इकोनॉमिक्स में सफलतापूर्वक अंडरग्रेजुएट डिग्री हासिल करने पर फ्रेफशनल्स या तो इकोनॉमिक जर्नलिज्म की ओर खुब करते हैं या इकोनॉमिक-फाइनेंशियल रिसर्च, बैंकिंग एवं कार्य के स्वरूप अपने विज्ञान का उनका रहना। यहाँ विज्ञान का सहभाग भी है। यदि वे लीक से थोड़ा अलग हट कर कुछ करना चाहते हैं तो उनके लिए जर्नलिज्म व लॉ इंस्टीट्यूट बैहर साबित हो सकती है। कई ऐसे एजीओ व एक्सपोर्ट ऑफिस हैं, जो इकोनॉमिक बैंकिंग डिलोमा वाले छात्रों को अपने यहाँ जाकर देते हैं। किसी कांलेज या यूनिवर्सिटी में टीचिंग में भी कारियर बनाया जा सकता है।

### आकर्षक सेलरी पैकेज

आजकल सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों जाह अर्थशास्त्रियों की मांग बढ़े पैमाने पर है। इसके चलते काम के साथ-साथ सेलरी पैकेज भी बेहद आकर्षक रूप अखिलया करता जा रहा है। आमतौर पर सरकारी सेवा में कार्यरक्षर अर्थशास्त्री को प्रतिमाह 20-25 हजार रुपए मिलते हैं। एक दो साल के अनुभव के पश्चात यही सेलरी 30-35 हजार रुपए प्रतिमाह तक पहुंच जाती है, जबकि प्रावेष्ट कंपनियों में सेलरी की रूपरेखा काफी कुछ संस्थाएं एवं कार्य के स्वरूप में निरन्तर करती है। इसके अलावा किसी कांलेज या यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स टीचर को 40-45 हजार रुपए प्रतिमाह की आमदानी होती है। आज कई ऐसे अर्थशास्त्री हैं, जिनका सालाना बेतान पैकेज लाखों में है। यदि वे लीक से थोड़ा खुद की फर्म स्थापित की है तो आमदानी की कोई निश्चित सीमा नहीं है।

### हायपर सेंसिटिव होते हैं

वे इस तरह के तंग करने वाले व्यवहार का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं और कई तरह की मानसिक बीमारियां पाल लेते हैं।



## क्या आप परेशान हैं आफिस के माहौल से

**आफिस** में सहकर्मियों द्वारा परेशान करने के बहुत से तरीके होते हैं। यहाँ जो डाग गया वो मग गया वाली बात ही लगती है। जो स्वभाव से नर्म, दब्के और हायर प्रेसर्सेंसिटिव होते हैं, वे इस तरह के तंग करने वाले व्यवहार का प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं और मन ही मन घुटते रहते हैं और कई तरह की मानसिक बीमारियां पाल लेते हैं।

### आप ही निशाने पर क्यों

- आपकी एक्सपर्ट कार्यप्रणाली को लेकर उनका असुरक्षित महसूस करना। उनके लिए एक्सपर्ट कार्यप्रणाली की कहानी कही जाती है। आपकी कार्य क्षमता के आगे गैर जरूरी न बन जाए।
- आपके फ्रैंकेनस इंसिटिउट से इंस्प्रिल आपको लेकर आए। आपका ध्यान अपने काम से हट जाए।
- कुछ लोग स्वभाव से ही नेटिविट प्रोफाइल से बदलते हैं, जिनका मांड़िड सेट ऐसा ही होता है। कुछ क्रांतीकारी स्वभाव वाले भी होते हैं।
- कैसे निपटें

- अपनी सोच पार्जिटिव रखें। किसी की नेटिविट बातों का अपने परिपरित



